



सामाजिक और आर्थिक विकास में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका

*¹डॉ. विमल कुमार

*¹असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, रामजी सहाय पी.जी. कालेज, रुद्रपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

ग्रामीण समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वे न केवल परिवार की आधारशिला होती हैं, बल्कि कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, घरेलू कार्य तथा सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति प्रदान करती हैं। ग्रामीण समाज भारतीय जनजीवन का मूल आधार है। इस शोध पत्र का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भूमिका का विश्लेषण करना तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं को उजागर करना है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण महिला, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण उद्योग, सरकारी योजनाएँ, पारिवारिक भूमिका।

प्रस्तावना

भारत मुख्यतः एक ग्रामीण समाज है, जहाँ लगभग 65 जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक परंपराएँ भारतीय जीवन की नींव हैं। इस ग्रामीण जीवन के केंद्र में महिलाएँ हैं, जो न केवल परिवार की धुरी हैं बल्कि कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग, हस्तकला, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण महिला का श्रम अदृश्य माना जाता है क्योंकि वह घरेलू कार्य और खेतों में योगदान देने के बावजूद “कमाने वाली” श्रेणी में दर्ज नहीं होती। परंतु वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण महिला समाज के आर्थिक ताने-बाने और सामाजिक मूल्यों को जीवित रखने में रीढ़ का काम करती है। आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण महिलाएँ कृषि उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, लघु उद्योग और स्वयं सहायता समूहों में सक्रिय हैं। सामाजिक दृष्टि से वे बच्चों के संस्कार, परिवार में स्वास्थ्य-स्वच्छता, पंचायत में सहभागिता और सामाजिक चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण हैं। फिर भी, उनके योगदान को अक्सर पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व संसाधनों तक सीमित पहुँच मिलती है।

शोध पद्धति

द्वितीयक स्रोत: पुस्तकों, शोध लेखों, सरकारी रिपोर्ट, जनगणना 2011, एन.सी.एस.के., एन.एफ.एच.एस. और एन.एस.एस.ओ. डेटा।

शोध समस्या

यद्यपि ग्रामीण महिलाएँ कृषि और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, फिर भी उन्हें अपेक्षित सम्मान, संसाधन और अवसर नहीं मिल पाते। उनकी श्रम शक्ति को अक्सर “अदृश्य” माना जाता है। यह शोध इस प्रश्न पर केंद्रित है कि ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक और सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान देती हैं? उनकी भूमिका को मान्यता और समर्थन क्यों नहीं मिलता? उनके सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय आवश्यक हैं?

शोध उद्देश्य

- ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भूमिका का अध्ययन करना।
- सामाजिक विकास में उनके योगदान का मूल्यांकन करना।

- महिलाओं के सामने उपस्थित बाधाओं और चुनौतियों की पहचान करना।
- महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु संभावित उपाय सुझाना।

परिकल्पना

- ग्रामीण महिलाएँ परिवार और समाज के आर्थिक-सामाजिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।
- शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच बढ़ने से उनकी भूमिका और प्रभाव अधिक सशक्त हो सकता है।
- पितृसत्तात्मक सोच और सीमित अवसर ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास में बाधक हैं।

आर्थिक विकास में भूमिका

कृषि कार्य में योगदान— ग्रामीण महिलाएँ बीज बोने, निराई-गुड़ाई, कटाई, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में सक्रिय भाग लेती हैं। लघु उद्योग एवं स्वरोजगार, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प, पापड़-बड़ी, अचार आदि घरेलू उद्योगों में भाग लेकर परिवार की आय बढ़ाती हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाएँ समूह बनाकर लघु ऋण लेती हैं और छोटे व्यवसाय चलाकर आत्मनिर्भर बनती हैं। गृह प्रबंधन वे संसाधनों का संतुलित उपयोग करके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती हैं।

सामाजिक विकास में भूमिका

परिवार व बच्चों का शिक्षण—संस्कार— महिलाएँ बच्चों की शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से समाज को बेहतर दिशा देती हैं। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामीण महिलाएँ परिवार में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधी आदतें विकसित करने में योगदान देती हैं। सामुदायिक भागीदारी, पंचायत, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न सामाजिक संगठनों में भाग लेकर सामाजिक जागरूकता फैलाती हैं। समानता और सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से समाज में लैंगिक समानता, निर्णय-निर्माण में भागीदारी और सामाजिक न्याय की स्थापना होती है।

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुझाव महत्वपूर्ण हैं—

- शिक्षा का प्रसारग्रामीण लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- वयस्क शिक्षा केंद्रों और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।
- स्वास्थ्य और पोषण
- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए।
- कुपोषण और अनिमिया से निपटने के लिए पोषण अभियान को और प्रभावी बनाया जाए।
- आर्थिक अवसरों का विस्तार
- महिला और माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को अधिक

समर्थन दिया जाए।

- कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और हस्तशिल्प में महिलाओं को प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराया जाए।
- समान वेतन और संसाधन
- समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए।
- भूमि और संपत्ति में महिलाओं के स्वामित्व अधिकारों को लागू किया जाए।
- राजनीतिक सहभागिता
- पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी को और सशक्त बनाया जाए।
- नेतृत्व क्षमता के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ।
- सामाजिक जागरूकता
- दहेज, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाए जाएँ।
- पुरुषों को भी महिला सशक्तिकरण अभियानों में शामिल किया जाए।
- तकनीकी सशक्तिकरण
- डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल और इंटरनेट प्रशिक्षण दिया जाए।
- ई-मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके उत्पादों को राष्ट्रीय व वैश्विक बाजार से जोड़ा जाए।

वर्तमान स्थिति

भारत की आधी जनसंख्या महिलाएँ हैं और इनमें से लगभग 70 प्रतिशत महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। ग्रामीण समाज की रीढ़ कही जाने वाली महिलाएँ कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, लघु उद्योग तथा परिवार के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आज भी ग्रामीण महिलाओं का श्रम भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, किंतु विडंबना यह है कि उन्हें उचित मान्यता, संसाधन और अवसर सीमित रूप में प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण और विकास योजनाओं ने उनकी भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत एक ग्रामीण राष्ट्र है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण समाज की रीढ़ ग्रामीण महिलाएँ हैं, जो परिवार की देखभाल, कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण और सरकार की योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है, परंतु उनके सामने अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कुरीतियाँ और आर्थिक संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भूमिका का विश्लेषण, उनकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के उपाय प्रस्तुत करना है। ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक और सामाजिक विकास की धुरी हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य,

रोजगार और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने से न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज और राष्ट्र का विकास संभव होगा। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं के प्रभाव से उनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

निष्कर्ष

ग्रामीण महिलाओं की भूमिका केवल "गृहिणी" तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक विकास की धुरी हैं। उनके बिना ग्रामीण समाज और राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। अतः शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और समान अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना आवश्यक है। ग्रामीण महिलाओं की भूमिका केवल गृहकार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि वे कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार की धुरी हैं। यदि उन्हें शिक्षा, संसाधन और समान अवसर प्रदान किए जाएँ तो वे न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के आर्थिक-सामाजिक विकास की गति को दोगुना कर सकती हैं।

ग्रामीण महिलाओं की भूमिका भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की आधारशिला है। वे कृषि कार्य, पशुपालन, लघु उद्योग और घरेलू प्रबंधन में अद्वितीय योगदान देती हैं। सामाजिक दृष्टि से वे परिवार की संस्कार वाहक, स्वास्थ्य संरक्षक और सामाजिक सुधार की प्रमुख धुरी हैं। यद्यपि उनका योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें अभी भी अशिक्षा, पितृसत्ता, आर्थिक असमानता और संसाधनों की कमी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय लेने की शक्ति मिले, तो वे न केवल अपने परिवार और गाँव का उत्थान कर सकती हैं बल्कि पूरे राष्ट्र की विकास गति को भी दोगुना कर सकती हैं।

References

1. Boserup (1970). Women's Role in Economic Development- London Earthscan-
2. Singh K- (2019). Rural Women in Development- Jaipur Rawat Publications.
3. National Sample Survey Organisation (NSSO-2019 & 20). Report on Employment in Rural India- Government of India.
4. National Family Health Survey- (NFHS 2021). Key Indicators for India- Ministry of Health and Family Welfare.
5. National Dairy Development Board- (NDDB2020). Annual Report on Dairy Sector in India.
6. Government of India (2022). Annual Report on Women Empowerment and Rural Development- Ministry of Rural Development.
7. WaterAid India (2017). Women and Sanitation% a Rural Perspective New Delhi.
8. World Bank (2020). Gender and Rural Development in India- Washington.
9. Ministry of Women and Child Development- (2021). Annual Report- Government of India.

10. Planning Commission/NITI Aayog (2019). Report on Rural Development and Women Empowerment.